राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा रुई की खरीद

1766. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या वाणिज्य मंत्री राष्ट्रीय कपडा निगम द्वारा रुई की खरीद के बारे में 14 मई, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3926 के उत्तर के संबंध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्न में मांगी गई समस्त जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : राष्ट्रीय वस्त्र निगम की 97 मिलो मे से 94 मिलों द्वारा जो कार्य कर रहीं थीं, 1973—75 वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में विभिन्न फर्मों से रुई की खरीद के बारे में जानकारी पहले से ही एकत्र कर ली गई है। फर्मवार जानकारी का संग्रह एवं मिलान अन्तर्ग्रस्त कार्य की मात्रा के अनुरूप नही है—एकत्रित की गई जानकारी पहले ही 200 से भी अधिक पन्नों मे है। जानकारी का सारांश निम्नोक्त प्रकार है :

1. वर्ष 1973—75 के दौरान मध्य प्रदेश की फर्मों से रुई की खरीद 2,42,851 गांठें तथा विभिन्न वजन वाले 13,331 बोरे थी।

2. 2,42,851 गाठों के बारे मे भुगतान निम्नोक्त प्रकार किया गया था :

> 3 महीनों के भीतर 75 प्रतिशत, 3 से 6 महीनों के भीतर 14 प्रतिशत, 6 से 9 महीनों के भीतर 4 प्रतिशत, 9 से 12 महीनों के भीतर 4 प्रतिशत और 12 महीनों के बाद 3 प्रतिशत—लेकिन कोई भुगतान शेष नही है ;

3. 13,331 बोरों के बारे में भुगतान निम्नोक्त प्रकार किए गए हैं :

> 3 महीनों के भीतर 83 प्रतिशत, 3 से 6 महीनों के भीतर 10 प्रतिशत, 6 से 9 महीनों के भीतर 3 प्रतिशत, 9 महीनों के बाद 4 प्रतिशत—लेकिन कोई भुगतान शेष नहीं है।

2. शेष तीन मिलों के संबंध में भी भुगतान किसी एक अथवा दूसरी सीमा अवधि के अन्तर्गत कवर हो गया होता।

विदेश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विदेशी बाजारों का सर्वेक्षण

1767. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश व्यापार को बढावा देने के लिए विदेशी बाजारों का गत वर्ष कोई सर्वेक्षण कराया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और इस काम के लिए भारतीय दल किन-किन देशों में भेजे गए ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) विदेशों में बाजार सर्वेक्षण साधारणतः सीधे सरकार द्वारा नहीं किए जाते। तथापि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान तथा व्यापार विकास प्रतिकरण

द्वारा किए गए बाजार-सर्वेक्षण के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

1. भारतीय विदेश व्यापार संस्थान :

(1) भारत तथा चैकोस्लोवाकिया और हंगरी के बीच व्यापार के विस्तार व आर्थिक सहयोग की संभावनाओं का सर्वेक्षण ।

(2) संयुक्त राज्य अमरीका मे चुनिंदा श्रम प्रधान इंजीनियरी मदों के संबंध मे बाजार सर्वेक्षण ।

(3) मैक्सिको तथा ब्राजील के साथ व्यापार के विस्तार तथा आर्थिक सहयोग की सभाव्यताओं का अध्ययन ।

(4) संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस बेल्जियम तथा स्पेन मे पटसन से बने माल के संबंध मे बाजार सर्वेक्षण ।

(5) थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर तथा फिलिपीन मे चुनिंदा इंजीनियरी उत्पादों का बाजार सर्वेक्षण ।

(6) ब्रिटेन, फ्रांस, बैनेलक्स तथा जर्मन संघीय गणराज्य मे जिलेटीन तथा ओस्सीन के बारे मे बाजार सर्वेक्षण ।

(7) सामान्यीकृत अधिमान प्रणाली के अन्तर्गत बेल्जियम, जर्मन संघीय गणराज्य तथा स्वीडन में रंग-रोगन, वार्निशों रंजक सामग्री तथा रंजक मध्यवर्ती पदार्थों के निर्यात के संबंध मे अध्ययन ।

2. व्यापार विकास प्राधिकरण :

(1) कनाडा मे प्लास्टिक उत्पादों के बारे मे सर्वेक्षण ।

(2) कनाडा मे इलैक्ट्रानिक्स के संबंध में सर्वेक्षण ।

(3) फिनलैंड मे खिलौनों तथा गुड़ियों के संबंध में सर्वेक्षण ।

(4) नार्वे में लकड़ी के फर्नीचर के संबंध में सर्वेक्षण ।

(5) फिनलैंड तथा नार्वे में बिजली के घरेलू उपकरणों के संबंध में सर्वेक्षण ।

(6) बेल्जियम तथा लक्जमबर्ग में साधित खाद्य पदार्थों के संबंध में सर्वेक्षण ।

(7) बेल्जियम तथा लक्जमबर्ग में हथकरघे के गृह सज्जा वस्त्रों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण ।

(8) डेनमार्क मे चमड़े के उत्पादों के संबंध मे सर्वेक्षण ।

उपरोक्त सर्वेक्षणों के अतिरिक्त, एक प्रबंध-परामर्शदाता फर्म द्वारा तकनीकी सहयोग हेतु राष्ट्रमंडलीय निधि की सहायता से अर्जेन्टीना, कोलम्बिया और पेरू मे चुनिंदा भारतीय उत्पादों के बारे में निर्यात बाजार विकास अध्ययन किया गया ।

निर्यात संवर्धन परिषदें आदि द्वारा भी उनसे सम्बन्धित उत्पादों के बारे मे समय समय पर बिक्री सह-अध्ययन दल आदि विभिन्न देशों को भेजे जाते रहे हैं ।

Rejection of Import Licences to Industrial Units in Gujarat

1768. SHRI ARVIND M. PATEL:
SHRI VEKARIA:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) the number of industrial units in Gujarat State whose import licences have been rejected by Government during the year 1975-76; and

(b) the reasons for rejection?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): (a) 729.

(b) Applications which were not received in accordance with the Import Policy, published in Import Trade Control Policy—Volumes I & II for the year 1975-76, as modified from time to time, were rejected. The